



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

19 आषाढ़ 1941 (श10)

(सं0 पटना 795) पटना, बुधवार, 10 जुलाई 2019

सं० 08/नि0था0-11-13/2015-सा०प्र0०-8634
सामान्य प्रशासन विभाग

संकल्प

28 जून 2019

श्री रविकान्त तिवारी, बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक-410/11, तत्कालीन उप विकास आयुक्त, सारण, छपरा के विरुद्ध आय से अधिक सम्पत्ति अर्जित करने के आरोपों पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम-1988 की धारा-13(2) सह पठित धारा-13(1)(ई0) के तहत विशेष निगरानी इकाई, पटना द्वारा कांड संख्या-02/15 दिनांक 20.12.2015 दर्ज करते हुए पत्रांक 1574 (अनु0) दिनांक 22.12.2015 द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को संसूचित किया गया।

(2) मामले की संवेदनशीलता एवं गंभीरता को देखते हुए विभागीय संकल्प ज्ञापांक-183 दिनांक 06.01.2016 द्वारा श्री तिवारी को निलंबित करते हुए विभागीय संकल्प ज्ञापांक-9945 दिनांक 19.07.2016 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। प्रमंडलीय आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल मुजफ्फरपुर को इस हेतु संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

(3) संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-1160 दिनांक 09.12.2016 द्वारा मामले का जांच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। जिसमें छपरा स्थित सरकारी आवास से 2.40 लाख नगद बरामद राशि एवं ज्ञात श्रोतों से अधिक सम्पत्ति अर्जित करने के आरोपों को प्रमाणित बताया गया। उक्त जांच प्रतिवेदन की प्रति संलग्न करते हुए विभागीय पत्रांक-17299 दिनांक 29.12.2016 द्वारा श्री तिवारी से लिखित अभिकथन/बचाव बयान की मांग की गयी, जिसके अनुपालन में उन्होंने लिखित अभिकथन (दिनांक 25.01.2017) समर्पित करते हुए आरोपों का प्रतिकार किया।

(4) कालान्तर में श्री तिवारी के बार्डक्य सेवानिवृत्ति (दिनांक 30.04.2018) को देखते हुए विभागीय संकल्प ज्ञापांक 5618 दिनांक 30.04.2018 द्वारा दिनांक 30.04.2018 (अप0) के प्रभाव से उन्हें निलंबन मुक्त किया गया तथा विभागीय आदेश ज्ञापांक-5619 दिनांक 30.04.2018 द्वारा इनके विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को बिहार पेंशन नियमावली के नियम-43'बी' के तहत सम्पत्तिवर्तित किया गया।

(5) अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर पर गठित आरोप, जाँच प्रतिवेदन एवं श्री तिवारी के स्पष्टीकरण की समीक्षा के क्रम में यह पाया गया कि प्रमाणित आरोपों के बचाव में श्री तिवारी द्वारा वर्ष 2015 के लिए परिसम्पत्ति एवं देयता का जो विवरण दिया गया है वह सही नहीं है।

(6) सम्यक विचारोपरांत श्री तिवारी, को बिहार पेंशन नियमावली के नियम-43 'बी' के तहत **शत-प्रतिशत (100%) पेंशन रोकने का दंड** विभागीय संकल्प ज्ञापांक-15181 दिनांक 22.11.2018 द्वारा अधिरोपित/संसूचित किया गया।

(7) उक्त शास्ति पर पुनर्विचार करने हेतु श्री तिवारी द्वारा एक पुनर्विचार आवेदन(दिनांक 18.01.2019) समर्पित किया गया, जिसमें उनके द्वारा कंडिकावार वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए अपने उपर लगे सभी आरोपों से इंकार करते हुए दंडादेश को निरस्त कर पेंशन भुगतान करने का अनुरोध किया गया है।

(8) संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जांच प्रतिवेदन, श्री तिवारी से प्राप्त पुनर्विचार आवेदन तथा उपलब्ध अभिलेखों की अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर पर समीक्षा के क्रम में यह स्पष्ट हुआ कि उनके द्वारा समर्पित पुनर्विलोकन अर्जी में किसी ऐसे नये तथ्यों/साक्ष्यों का उल्लेख नहीं किया गया है, जिस पर की विचार किया जा सके। बल्कि जिन तथ्यों का उल्लेख किया गया है उसका उल्लेख उनके द्वारा पूर्व में भी अपने लिखित अभिकथन में किया गया था।

(9) अतएव उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में सम्यक विचारोपरांत श्री रविकान्त तिवारी, बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक-410/11, तत्कालीन उप विकास आयुक्त, सारण, छपरा(सम्प्रति सेवा निवृत्त) के पुनर्विचार आवेदनों को अस्वीकृत करते हुए विभागीय संकल्प ज्ञापांक-15181 दिनांक 22.11.2018 द्वारा अधिरोपित दंड यथा **शत-प्रतिशत (100%) पेंशन रोकने का दंड** को यथावत रखा जाता है।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
शिवमहादेव प्रसाद,
सरकार के अवर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 795-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>